संक्षिप्त खबरें

वियतनाम में बस-ट्रक की टक्कर में पांच लोगों की मौत

हनोई। वियतनाम के उत्तरी तुयेन क्वांग प्रांत में राष्ट्रीय राजमार्ग पर सोमवार देर रात एक बस और कंटेनर ट्रक के बीच हुई टक्कर में पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वियतनाम समाचार एजेंसी ने यह जानकारी दी है। एजेंसी ने बताया कि दुर्घटना स्थानीय समयानुसार देर रात लगभग 1ः40 बजे हुई जब स्लीपर बस हा गियांग और तुयेन क्वांग प्रांतों के राजमार्ग संख्या दो पर चल रही थी कि विपरीत दिशा में हाई फोंग शहर से हा गियांग प्रांत की ओर जा रहा कंटेनर ट्रक बस से टकरा गया। दुर्घटना में पांच अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें अस्पताल ले जाया गया। स्थानीय समाचार वेबसाइट वीएनएक्सप्रेस ने बताया कि दुर्घटना में ट्रक पलट गया जबकि बस का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। दुर्घटना की जांच की जा रही है।

निर्माणाधीन पुल का डेक गिरने से एक की मौत

पेरिस। फ्रांस के टूलूज़ शहर की मेट्रो लाइन पर सोमवार को निर्माणाधीन पुल का डेक गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। स्थानीय मीडिया ने यह जानकारी दी है। मीडिया आउटलेट ला डेपेच डू मिडी ने बताया, ÷सोमवार को टूलूज़ मेट्रो की लाइन सी के टिसियो निर्माण स्थल पर निर्माणाधीन पुल के डेक का एक हिस्सा ढह गया।÷ ÷एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और दो अन्य पूरी तरह से आपातकालीन स्थिति में हैं।÷ रिपोर्ट में कहा गया है कि टिसियो टूलूज़ महानगरीय क्षेत्र के लिए सार्वजनिक परिवहन प्राधिकरण है। ढहा हुआ पुल का डेक फ्रांस के चौथे सबसे बड़े शहर टूलूज़ के केंद्र से लगभग 14 किमी दूर लाबेगे में स्थित है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मरने वालों की संख्या की पुष्टि के लिए तलाशी अभियान अभी भी जारी है।

मेक्सिको में दो वाहनों की टक्कर में नौ लोगों की मौत

मेक्सिको सिटी। मेक्सिको के दक्षिणपूर्वी राज्य क्विंटाना रू में सोमवार तड़के एक ट्रैक्टर-ट्रेलर की अंतरनगरीय परिवहन वैन से हुई आमने-सामने की टक्कर में तीन नाबालिगों सहित नौ लोगों की मौत हो गई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। क्विंटाना रू राज्य के अटॉर्नी जनरल कार्यालय के एक बयान के अनुसार, संघीय राजमार्ग 307 पर हुई इस दुर्घटना में छह लोग घायल भी हुए है। दुर्घटना स्थानीय समयानुसार सुबह 4ः00 बजे के आसपास राजमार्ग के रिफोर्मा एग्रारिया-प्यूर्टो जुआरेज़ खंड पर, एक्स-हेज़ल चौराहे के पास हुई। ट्रेलर के चालक ने वाहन पर से अपना नियंत्रण खो दिया और ट्रेलर वैन से टकरा गया। स्थानीय मीडिया द्वारा प्रकाशित प्रारंभिक रिपोर्टों के अनुसार, वैन में तुरंत आग लग गई, जबकि ट्रेलर चालक वाहन को घटनास्थल से भगा ले गया। क्विंटाना रू के गवर्नर मारा लेज़ामा ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में इस त्रासदी पर शोक व्यक्त किया और मोटर चालकों से अत्यधिक सावधानी बरतने का आह्वान किया क्योंकि राजमार्ग का वह हिस्सा अस्थायी रूप से बंद किया हुआ है।

तेहरान-मास्को अंतरिक्ष सहयोग के बारे में अमेरिकी दावे खारिज

तेहरान। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नासिर कनानी ने मॉस्को के साथ तेहरान के अंतरिक्ष सहयोग के बारे में अमेरिकी अधिकारियों के दावों को आधारहीन बताते हुए खारिज कर दिया। कनानी अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर के दावों पर प्रतिक्रिया दे रहे थे। मिलर ने रूस द्वारा हाल ही में ईरानी उपग्रह के प्रक्षेपण को दोनों देशों के बीच बढ़ते सैन्य सहयोग एक और उदाहरण बताया था। इसे उन्होंने यूक्रेन, ईरान के पड़ोसियों व अंतरराष्ट्रीय समुदाय के लिए खतरा कहा था। शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने सोमवार को तेहरान में संवाददाताओं से बात करते हुए कहा कि ईरान और रूस के बीच रक्षा और सैन्य सहयोग अंतरराष्ट्रीय कानूनों और नियमों के तहत दोनों देशों के सामान्य हितों पर आधारित है। कनानी ने जोर देकर कहा, अंतर्राष्ट्रीय नियमों और कानूनों के तहत सहयोग दोनों देशों का अधिकार है। हम अमेरिकी अधिकारियों के आधारहीन दावों को खारिज करते हैं।रूस के साथ हमारा सहयोग किसी तीसरे पक्ष के खिलाफ नहीं है। ईरान ने गुरुवार को पूर्वी रूस में रूस के सोयुज रॉकेट प्रक्षेपण के माध्यम से पार्स-1 नामक अपने उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया।

ट्विटर के पूर्व सीईओ ने मस्क पर किया मुकदमा

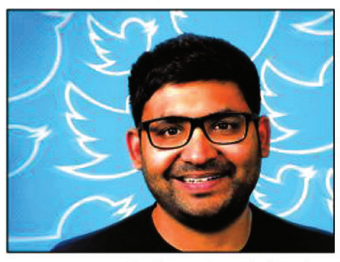

सैन फ्रांसिस्को। ट्विटर (अब एक्स) के पूर्व सीईओ पराग अग्रवाल सहित तीन कर्मचारियों ने एलन मस्क पर 128 मिलियन डॉलर नहीं चुकाने को लेकर उनके खिलाफ मुकदमा दायर करने का ऐलान किया है। पराग अग्रवाल, मुख्य वित्तीय अधिकारी नेड सेगल पूर्व ट्विटर कानूनी और नीति प्रमुख विजया गड्डे और पूर्व ट्विटर जनरल काउंसिल सीन एडगेट ने एलन मस्क के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। एक फॉलोवर ने पोस्ट किया कि पराग अग्रवाल ने एलन मस्क पर मुकदमा दायर किया है, तो इस पर मंगलवार को मस्क ने सिर्फ एक इमोजी डालकर अपनी प्रतिक्रिया दी। मुकदमे में दावा किया गया कि टेस्ला के सीईओ ने सार्वजनिक रूप से लगभग 200 मिलियन डॉलर के उनके भुगतान को रोकने की कसम खाकर उनके प्रति विशेष गुस्सा दिखाया, जब उन्होंने 2022 में 44 बिलियन डॉलर में ट्विटर का अधिग्रहण किया। अमेरिकी जिला न्यायालय में दायर मुकदमा में कहा गया है, मस्क के नियंत्रण में ट्विटर कर्मचारियों, मकान मालिकों, विक्रेताओं और अन्य लोगों को परेशान करने वाला एक उपहास बन गया है। मस्क अपने बिलों का भुगतान नहीं करते हैं, उनका मानना है कि नियम उन पर लागू नहीं होते हैं, और जो कोई भी उनसे असहमत है, उसके साथ दुर्व्यवहार करने के लिए अपने धन और शक्ति का उपयोग करते हैं। अक्टूबर 2022 में, मस्क ने अग्रवाल, गड्डे और सेगल को सूचित किया कि कंपनी के साथ उनका संबंध खत्म कर दिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, जब तीनों शीर्ष अधिकारियों ने कंपनी छोड़ी तो उनके पास 100 मिलियन डॉलर से ज्यादा का एग्जिट पैकेज था।

पीएम मोदी ने थाईलैंड में भारतीय दूतावास के एक्स पर किए गए एक पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा

भारत-थाईलैंड के बीच आध्यात्मिक सेतु हैं बुद्ध के आदर्श

एजेंसी

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि भगवान बुद्ध के आदर्श भारत और थाईलैंड के बीच एक आध्यात्मिक सेतु के रूप में काम करते हैं, जो दोनो देशों के बीच गहरे संबंधों को बढ़ावा देता है।

पीएम मोदी थाईलैंड में भारतीय दूतावास के एक्स पर किए गए एक पोस्ट पर प्रतिक्रिया दे रहे थे, जिसमें कहा गया था कि दस लाख थाई श्रद्धालुओं ने भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों के दर्शन किए हैं। इन पवित्र अवशेषों को एक प्रदर्शनी के तहत थाईलैंड के बैंकॉक में 22 फरवरी से तीन मार्च तक प्रदर्शित किया गया। मोदी ने कहा, मुझे खुशी है कि भक्तों के पास आध्यात्मिक रूप से समृद्ध अनुभव था और मैं भक्तों से चियांग माई, उबोन रत्चाथानी और क्राबी में मत्था टेकने का आग्रह करता हूं, जहां आने वाले दिनों में अवशेष स्थापित किए जाएंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज सियोल में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रीय सुरक्षा निदेशक चांग हो-जिन से मुलाकात की। उन्होंने ट्वीट किया, भारत-प्रशांत और समकालीन क्षेत्रीय व वैश्विक मुद्दों पर एक चर्चा हुई।

रूसी विदेश मंत्री ने की भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर की तारीफ

मॉस्को। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की सराहना की है। रूसी शहर सोच्चि में वर्ल्ड यूथ फोरम में लावरोव से पूछा गया कि यूक्रेन जंग के बीच भारत रूस से तेल क्यों खरीद रहा है। इस पर लावरोव ने कहा- मेरे दोस्त जयशंकर ने इसका बखूबी जवाब दिया था। इसके बाद लावरोव ने जयशंकर के बयान को याद करते हुए कहा- भारत के विदेश मंत्री से ह में ऐसा ही सवाल किया गया था। तब जयशंकर ने उन्हें अपने काम से मतलब रखने की सलाह दी थी। साथ ही उन्हें याद दिलाया था कि पश्चिमी देश रूसी फेडरेशन ने कितना तेल खरीद रहे हैं।

लावरोव बोले- रूस ने शीत युद्ध के दौरान भारत का साथ दिया। भारत के साथ रिश्तों पर बात करते हुए लावरोव ने कहा- रूस-भारत हमेशा से अच्छे दोस्त रहे हैं। कोल्ड वॉर के दौरान जब पश्चिमी देशों ने भारत को हथियार देने रोक दिए थे, तब मॉस्को ने भारत का साथ दिया था। रूस ने भारत के साथ हाई-टेक मिसाइल ब्रह्मोस का जॉइंट प्रोडक्शन भी शुरू किया। दरअसल, रूस-यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद पश्चिमी देशों ने रूस पर पाबंदियां लगा दी थीं। ऐसे में यूरोप ने तेल खरीदने के लिए मिडिल ईस्ट का सहारा लिया था। हालांकि, इस बीच भारत ने रूस से तेल खरीदना जारी रखा था। इसका कुछ पश्चिमी देशों ने विरोध भी किया था।

भारत ने 2020 में रूस से अपनी जरूरत का सिर्फ 2 प्रतिशत कच्चा तेल खरीदा था। रूस-यूक्रेन युद्ध शुरू होने से ठीक पहले 2021 में टोटल सप्लाई 16त्न हो गई और 2022 में सप्लाई बढ़कर 35त्न तक पहुंच गई। फिलहाल भारत रूस से अपनी जरूरत का 40त्न क्रूड ऑयल खरीद रहा है। 2023 में जनवरी से सितंबर के बीच भारत ने रूस से ?43,782 प्रति टन की रेट से तेल खरीदा है (इसमें शिपिंग और दूसरे चार्ज शामिल हैं।)। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने सरकारी आंकड़ों के हवाले से इसकी जानकारी दी थी।

हाल ही में रूस से भारत के तेल खरीदने के अपने फैसले का समर्थन करते हुए जयशंकर ने कहा था- रूस से कच्चा तेल खरीदना बिल्कुल सही फैसला है। जब यूक्रेन में युद्ध शुरू हुआ था तो मिडिल ईस्ट के देशों ने यूरोप के देशों को प्राथमिकता दी थी। हमारे पास ऐसे में क्या विकल्प था? या तो हमें तेल नहीं मिलता क्योंकि सारा तेल यूरोप के देश खरीद रहे थे या फिर हम अधिक कीमतों पर तेल खरीदते। जयशंकर ने कहा- ऐसी स्थिति में भारत ने रूस से कच्चा तेल खरीद कर बाजार में तेल की कीमतों को स्थिर करने का काम किया। रूस के साथ भारत के बहुत ही स्थिर और दोस्ताना संबंध है और रूस ने कभी भी हमारे हितों को नुकसान नहीं पहुंचाया।

डोनाल्ड ट्रंप अब लड़ सकेंगे राष्ट्रपति चुनाव, सुप्रीम कोर्ट ने हटाया प्रतिबंध

वाशिंगटन। अमेरिका के उच्चतम न्यायालय ने कैपिटल (संसद परिसर) दंगे के लिए पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जवाबदेह ठहराने संबंधी प्रयासों को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव लड़ सकेंगे। इससे पहले एक अदालत ने ट्रंप को कोलोराडो के रिपब्लिकन प्राथमिक मतदान से अयोग्य घोषित कर दिया था। अमेरिकी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश ने सर्वसम्मति से निचली अदालत के उस फैसले को पलट दिया कि ट्रंप को छह जनवरी, 2021, कैपिटल दंगा मामले में उनकी कथित भूमिका के कारण 14 वें संशोधन के तहत सार्वजनिक पद धारण करने से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। कोलोराडो के सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी तरह के पहले फैसले में कहा था कि प्रावधान, धारा 3, ट्रंप पर लागू की जा सकती है। इससे पहले किसी भी अदालत ने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार पर धारा 3 लागू नहीं की थी।

युद्धविराम की कार्रवाई में लाएं तेजी

एजेंसी

वाशिंगटन। अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस ने इजराइल के कैबिनेट सदस्यों से मुलाकात कर सीजफाइयर की कार्रवाई में तेजी लाने को कहा है। उन्होंने फिलिस्तीनी नागरिकों को सभी प्रकार की मानवीय सहायता सुनिश्चित किए जाने का भी आग्रह किया।

इजराइल के पूर्व रक्षा मंत्री और उप-प्रधानमंत्री बेनी गैंट्ज़ के साथ हैरिस की मुलाकात सोमवार को हुई जिसमें उन्होंने इजरायल और हमास के बीच तत्काल युद्धविराम के लिए आह्वान किया। व्हाइट हाउस द्वारा जारी बैठक के एक रीडआउट में कहा गया है, उपराष्ट्रपति ने बंधक समझौते को हासिल करने की तात्कालिकता पर चर्चा की और बंधक वार्ता के लिए इज़राइल के दृष्टिकोण का स्वागत किया। उन्होंने कहा, उन्होंने हमास से शर्तों को स्वीकार करने का आह्वान किया, जिसके तहत बंधकों की रिहाई के बाद तत्काल छह सप्ताह का युद्धविराम होगा। रीडआउट में कहा गया है कि हैरिस ने गाजा में मानवीय स्थितियों और उत्तरी गाजा में एक सहायता काफिले के आसपास हाल ही में हुई भीषण त्रासदी के बारे में अपनी गहरी चिंता व्यक्त की।

इस घटना में एक सहायता काफिले से भोजन प्राप्त करने की कोशिश कर रहे कई फिलिस्तीनियों पर हमला हुआ था जिसमें सौ से ज्यादा लोग मारे गए। जब से इजराइल ने गाजा में अपना आक्रमण शुरू किया है, तब से फिलिस्तीनी नागरिकों की मौत की संख्या 30,000 से अधिक हो गई है। इज़रायली सेना ने रविवार को कहा था मारे गए लोगों में से अधिकांश की मौत भगदड़ से हुई, जबकि फिलिस्तीन द्वारा संचालित स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा कि जिन लोगों को अस्पतालों में भेजा गया था, उन्हें गोली मार दी गई।

रीडआउट में आगे कहा गया है कि गैंट्ज़ के साथ बैठक के दौरान हैरिस ने इजरायल से गाजा में मानवीय सहायता के प्रवाह को बढ़ाने और जरूरतमंद लोगों तक इसका सुरक्षित वितरण सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका और अंतरराष्ट्रीय भागीदारों के सहयोग से अतिरिक्त उपाय करने का आग्रह किया। युद्ध से निपटने के तरीके को लेकर राष्ट्रपति बाइडेन और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच बढ़ती दरार के बीच गैंट्ज़ की यात्रा हुई है। गैंट्ज़ नेतन्याहू के राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी हैं, लेकिन दोनों एक समझौते पर पहुंचे हैं, जिसके तहत वे हमास के खिलाफ सैन्य अभियान की योजना बनाने में सत्ता साझा करने पर सहमत हुए।

मालदीव ने भारत की सेना को बाहर कर चीन से कर लिया सैन्य समझौता

माले। भारत के साथ जारी विवाद के बीच मालदीव ने चीन के साथ एक और समझैता किया है। चीन ने सोमवार को मालदीव के साथ मजबूत द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए मुफ्त सैन्य सहायता प्रदान करने संबंधी रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता ऐसे समय में हुआ है जब राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने मालदीव से भारतीय सैन्य कर्मियों को बाहर करने के लिए डेडलाइन तय की है। एक दिन पहले मालदीव के रक्षा मंत्री मोहम्मद घासन मौमून ने दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करने के लिए चीन के अंतरराष्ट्रीय सैन्य सहयोग कार्यालय के उप निदेशक मेजर जनरल झांग बाओकुन से मुलाकात की। मालदीव के रक्षा मंत्रालय ने अपने एक्स हैंडल पर बताया कि मौमून और मेजर जनरल बाओकुन ने मालदीव गणराज्य को मजबूत द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए चीन के सैन्य सहायता के प्रावधान पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

ताइवान के श्रम मंत्री के बयान से खड़ा हुआ विवाद, मांगी माफी

एजेंसी

ताइपे सिटी। ताइवान के श्रम मंत्री सू मिंगचुन के एक बयान से विवाद खड़ा हो गया है। भारतीयों को लेकर की गई नस्लीय टिप्पणी को लेकर ताइवान के विदेश मंत्रालय को भारत से माफी मांगनी पड़ी। दरअसल एक इंटरव्यू के दौरान मिंगचुन ने कहा था कि वह अपने देश की ताकत बढ़ाने के लिए भारत में पूर्वोत्तर के राज्यों के मजदूरों को भर्ती करेंगे क्योंकि उनकी शक्ल और खाने की आदतें ताइवान के समान ही हैं। इसके अलावा यहां ईसाी आबादी है।

ताइवान के विदेश मंत्रालय ने भी उनके इस बयान से दूरी बना ली है। वहीं ताइवान ने सफाई देते हुए कहा है कि सभी मजदूरों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। बता दें कि अगले एक साल के अंदर ही भारतीय कामगारों का पहला बैच ताइवान पहुंचने वाला है। ताइवान के अधिकारियों का कहना है कि भारत के दूसरे प्रदेशों से भी भर्तियां की जाएंगी। मामले के जानकार लोगों का कहना है कि पहली बार किसी देश ने कहा है कि भारत के किसी विशेष राज्य से भर्तियां की जाएंगी।

यह एक नस्लीय टिप्पणी है। किसी के भी साथ खाने की आदतें, शक्ल या फिर धर्म की वजह से भेदभाव नहीं किया जा सकता। कई पश्चिमी एशिया के देश पिछले पांच दशकों से भारत के लोगों को भर्ती कर रहे हैं। हालांकि आज तक किसी भी देश ने इस तरह की बात नहीं रखी कि वह किसी विशेष राज्य या धर्म को प्राथमिकता देने वाला है। यहां तक की खाड़ी के मुस्लिम देशों में भी बड़ी संख्या में भारतीय कामगार जाते हैं। इन देशों ने भी कभी धर्म के आधार पर भर्ती की बात नहीं कही। बता दें कि पिछले महीने ही भारत और ताइवान के बीच समझौता हुआ है जिसके तहत भारतीय कामगारों को ताइवान में अलग-अलग क्षेत्रों में काम देने की बात कही गई है।

गर्भपात का संवैधानिक अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बना फ्रांस

एजेंसी

पैरिस। फ्रांस दुनिया का ऐसा पहला देश बन गया है जिसने गर्भपात के अधिकार को अपने संविधान में जगह दे दी है। बता दें कि दुनियाभर एंटी अबॉर्शन ग्रुप इस फैसले का विरोध कर रहे थे। बावजूद इसके मैक्रों की सरकार ने सख्ती दिखाई और बड़ा फैसला ले लिया। फ्रांस की संसद में इस विधेयक के पक्ष में 780 वोट पड़े। वहीं विरोध में केवल 72 वोट ही पड़े। बहुत सारे अबॉर्शन राइट्स ऐक्टिविस्ट पैरिस में इकट्ठा हुए थे और इस फैसले का स्वागत कर रहे थे।

अगर सर्वे की बात करें तो अमेरिका और अन्य किसी भी देश से ज्यादा गर्भपात के अधिकार को फ्रांस में समर्थन मिला। यहां करीब 80 फीसदी लोगों ने इस अधिकार को सही माना। फ्रांस के प्रधानमंत्री गैब्रिएल अटाल ने कहा, हम सभी महिलाओं को एक संदेश दे रहे हैं। आपका शरीर सिर्फ आपका है। इस बारे में फैसला लेने के अधिकार भी आपके अलावा और किसी को नहीं है। बता दें कि फ्रांस में महिलाओं को गर्भपात का कानूनी अधिकार 1974 से ही मिला हुआ है। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में रो वी वेड के फैसले को पलटते हुए गर्भपात के कानूनी अधिकार को खत्म कर दिया था। सीएनएन के मुताबिक फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने कहा कि उन्होंने पहले ही महिलाओं से वादा किया था कि वे गर्भपात के लिए संवैधानिक अधिकार देंगे।

इस संशोधन विधेयक में कहा गया है कि फ्रांस में गर्बपात की गारंटी के साथ स्वतंत्रता है। बताया जा रहा है कि फ्रांस की सरकार महिला दिवस के मौके पर बड़ा कार्यक्रम आयोजित करेगी और इस फैसले का जश्न मनाएगी। फ्रांसीसी वामपंथी इसे अपनी बड़ी जीत मान रहे हैं। कैथोलिक चर्च ने भी इस विधेयक का विरोध किया था।

हिजबुल्लाह के मिसाइल हमले में भारतीय की मौत

एजेंसी

बेरूत। लेबनान से दागी गई एक एंटी-टैंक मिसाइल के इजराइल के उत्तरी सीमावर्ती मार्गालियोट समुदाय के पास एक बगीचे में गिरने से एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई, जबकि दो अन्य घायल हो गए। समाचार एजेंसी के मुताबिक, घटना सोमवार की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि तीनों भारतीय केरल के रहने वाले थे। पीड़ित की पहचान केरल के कोल्लम के 31 वर्षीय पैट निबिन मैक्सवेल के रूप में हुई।

मैक्सवेल कथित तौर पर दो महीने पहले इज़राइल पहुंचे थे और हमले के समय एक खेत में काम कर रहे थे। उनकी पांच साल की बेटी और उनकी पत्नी जीवित हैं, जो एक और बच्चे की उम्मीद कर रही हैं। दोनों घायल भारतीयों की पहचान बुश जोसेफ जॉर्ज और पॉल मेल्विन के रूप में हुई। बचाव सेवा मैगन डेविड एडोम (एमडीए) के प्रवक्ता जकी हेलर ने बताया कि मिसाइल ने सोमवार सुबह करीब 11 बजे इजराइल के उत्तर में गैलील क्षेत्र में मोशव (सामूहिक कृषि समुदाय) मार्गालियट में एक बागान पर हमला किया।

एक आधिकारिक सूत्र ने कहा, चेहरे और शरीर पर चोट लगने के बाद जॉर्ज को पेटा टिकवा के बेलिन्सन अस्पताल ले जाया गया। उनका ऑपरेशन किया गया, उनकी हालत में सुधार हो रहा है और उन्हें निगरानी में रखा गया है। वह भारत में अपने परिवार से बात कर सकते हैं। मेल्विन मामूली रूप से घायल हो गए और उन्हें उत्तरी इज़राइली शहर सफ़ेद के ज़वि अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वह केरल के इडुक्की जिले से हैं। माना जाता है कि यह हमला लेबनान में शिया हिजबुल्लाह गुट द्वारा किया गया था, जो गाजा पट्टी में चल रहे युद्ध के बीच हमास के समर्थन में 8 अक्टूबर से रोजाना उत्तरी इज़राइल पर रॉकेट, मिसाइल और ड्रोन लॉन्च कर रहा है। घटना पर टिप्पणी करते हुए, पीड़ित के पिता पाथ्रोस मैक्सवेल ने कहा कि उन्हें शाम लगभग 4.30 बजे उनकी बहू का फोन आया, जिसमें बताया गया कि उनके बेटे का एक्सीडेंट हो गया है।

बाद में करीब साढ़े 12 बजे उन्हें बेटे की मौत की सूचना दी गयी। पीड़िता के पिता ने कहा, ÷मेरे तीन बच्चे हैं, जबकि दो इज़राइल में हैं, एक अबू धाबी में काम करता है।÷ उन्होंने कहा, पैट निबिन की एक बेटी है। वह पांच साल की है। उसकी पत्नी सात महीने की गर्भवती है। इस बीच, भारत में इजरायली दूतावास ने भारतीय नागरिक की मौत पर दुख व्यक्त किया और कहा कि इजरायली चिकित्सा संस्थान हमले में घायल हुए लोगों की सेवा में हैं। एक एक्स पोस्ट में दूतावास ने कहा, शांतिपूर्ण खेती कर रहे कृषि श्रमिकों पर शिया आतंकी संगठन हिजबुल्लाह द्वारा किए गए कायरतापूर्ण आतंकी हमले के कारण एक भारतीय नागरिक की मौत और दो अन्य के घायल होने से हम गहरे सदमे में हैं और दुखी हैं। कल दोपहर को मार्गालियट के उत्तरी गांव में बाग।

उन्होंने यह भी कहा कि हमारी प्रार्थनाएं और विचार स्वाभाविक रूप से शोक संतप्त परिवारों और घायलों के प्रति हैं। इजरायली चिकित्सा संस्थान पूरी तरह से उन घायलों की सेवा में हैं जिनका इलाज हमारे सबसे अच्छे चिकित्सा कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा है। इजरायल सभी नागरिकों, चाहे इजरायली हो या विदेशी, का समान रूप से सम्मान करता है। जो आतंकवाद के कारण घायल या मारे गए हैं।

चीन ने भारत से तीन गुना बढ़ाया अपना रक्षा बजट

एजेंसी

बीजिंग। चीन लगातार अपना रक्षा बजट बढ़ा रहा है और इस साल चीन ने अपने रक्षा बजट में बीते पांच साल में सबसे ज्यादा 7.2 फीसदी की बढ़ोतरी की है। इस बढ़ोतरी के साथ ही चीन का रक्षा बजट इस साल 1.67 ट्रिलियन युआन (231 अरब डॉलर) पहुंच गया है।

मीडिया रिपोर्ट्स में चीन के वित्त मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट के आधार पर ये दावा किया गया है। चीन, अमेरिका के बाद रक्षा बजट पर सबसे ज्यादा खर्च करने वाला दूसरा देश है। सीमा पर भारत और चीन के बीच लंबे समय से तनाव है और दोनों देशों के सैनिक कई बार आमने-सामने आ चुके हैं। हालांकि सेना को आधुनिक बनाने के लिहाज से चीन, भारत से कहीं आगे दिख रहा है। इसकी वजह चीन का भारी-भरकम रक्षा बजट है, जो भारत के रक्षा बजट से तीन गुने से भी ज्यादा है। भारत का साल 2024 के लिए रक्षा बजट 6,21,541 करोड़ रुपये है, जो कि करीब 74.8 अरब डॉलर होता है। वहीं चीन का 2024 का बजट करीब 232 अरब डॉलर है, जो कि भारत के बजट से बहुत ज्यादा है।

चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपनी सेना पीएलए को आधुनिक बनाने के लिए 2027 का लक्ष्य तय किया है और बजट में बढ़ोतरी की वजह भी यही है। साथ ही चीन का दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस, जापान समेत कई देशों से विवाद चल रहा है। वहीं सीमा विवाद के चलते भारत से भी चीन के संबंध बुरे दौर से गुजर रहे हैं। यही वजह है कि चीन लगातार अपनी सेना को आधुनिक बना रहा है। खासकर चीन अपनी नौसेना में काफी निवेश कर रहा है और आज चीन की नौसेना जहाजों के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है। चीन एयरक्राफ्ट कैरियर का भी निर्माण कर रहा है और हिंद महासागर के कई देशों में चीन ने अपने अड्डे बना लिए हैं।

चीन की चुनौतियां भी बढ़ीं

चीन की सेना सैनिकों की संख्या के मामले में सबसे बड़ी है। साथ ही चीन की सेना में दो रॉकेट फोर्स हैं और यही रॉकेट फोर्स ही परमाणु हथियारों का संचालन संभालती है। चीन पर आरोप हैं कि वह चुपचाप अपने रॉकेट फोर्स का विस्तार कर रहा है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि चीन का रक्षा बजट बताए जा रहे आंकड़ों से कहीं ज्यादा है क्योंकि चीन अपने सैन्य रिसर्च और डेवलेपमेंट के बजट को रक्षा बजट में शामिल नहीं करता है। हालांकि जहां एक तरफ चीन लगातार अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहा है, वहीं उसकी चुनौतियां भी बढ़ी हैं। चीन ने बीते दिनों अपने रक्षा प्रमुख को बिना कोई वजह बताए पद से हटा दिया था। साथ ही कई शीर्ष जनरलों को भी बदला गया है। इससे साफ है कि चीन की सेना में समस्याएं भी हैं।

अमेरिका से अभी भी बहुत पीछे है चीन

चीन के बढ़ते दबदबे से अमेरिका भी चिंतित है। हालांकि अभी भी रक्षा बजट के मामले में अमेरिका, चीन से सबसे काफी आगे है। अमेरिका का पिछले साल रक्षा बजट 886 अरब डॉलर था। चीन की बढ़ती चुनौती को देखते हुए अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन की सेना को मजबूत करने में जुटा है। वहीं भारत के साथ भी अमेरिका रणनीतिक सहयोग बढ़ा रहा है।

क्राउन प्रिंस ने सऊदी अरब की मस्जिदों में इफ्तार पार्टियों का आयोजन करने पर लगाई रोक

एजेंसी

आबूधाबी। सऊदी अरब ही वो देश है, जहां पर इस्लाम की सबसे पवित्र माने जाने वाली दो जगहें मक्का और मदीना मौजूद हैं। सऊदी किंग इन मस्जिदों के संरक्षक भी हैं। इस वजरमजान का पवित्र महीना शुरू होने से पहले ही सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद ने एक ऐसा आदेश दिया है जो हैरान करने वाला है।

एमबीएस के नाम से मशहूर क्राउन प्रिंस ने सऊदी अरब की मस्जिदों में इफ्तार पार्टियों का आयोजन करने पर रोक लगा दी है। सऊदी अरब खुद को अघोषित तौर पर खुद को इस्लाम के अगुवा के तौर पर पेश करता है। अब वहीं के क्राउन प्रिंस ने देश की मस्जिदों में इफ्तार पार्टियों को प्रतिबंधित कर दिया है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब मोहम्मद बिन सलमान ने इस तरह का आदेश दिया है। दरअसल क्राउन प्रिंस सऊदी अरब को एक रुढ़िवादी मुस्लिम देश से माडरेट इस्लामिक मुल्क की ओर ले जाना चाहते हैं। आइए देखते हैं कि कट्टर वहाबी आंदोलन से निकला सऊदी अरब किस तरह मोहम्मद बिन सलमान के नेतृत्व में मॉडरेट इस्लाम की ओर बढ़ रहा है।

बदलेगी देश की सूरत

तेल से आ रहे पैसे ने सऊदी राजशाही की इस मंशा को आगे बढ़ाने में खूब मदद की, लेकिन साल 2001 में अमेरिका के न्यूयार्क में 9/11 को हुए हमले के बाद दुनिया में कट्टर इस्लाम को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया हुई। यही वो समय था जब सऊदी राजशाही में परिवर्तन हुआ और सलमान अब्दुल बिन अजीज सऊदी के किंग बने और उनके बेटे मोहम्मद बिन सलमान क्राउन प्रिंस बने। मोहम्मद बिन सलमान ने धीरे-धीरे सत्ता पर अपनी पकड़ बनानी शुरू की और फिर देश में ऐसे सुधार शुरू किए जो कभी सऊदी अरब में सोचे भी नहीं जा सकते थे।

कभी रुढ़िवादी इस्लाम के लिए जाना जाता था सऊदी

अल सऊद परिवार ने जब ऑटोमन साम्राज्य से निकलकर आजाद देश की स्थापना की उसके बाद से ही इसकी पहचान एक कट्टर इस्लामिक मुल्क के रूप में बनाए रखने पर जोर दिया। देश में कड़े इस्लामिक कानून लागू किए गए। चोरी करने पर हाथ-पैर काटना और सार्वजनिक सजा-ए-मौत दी जाने लगी। 1979 में पड़ोसी देश ईरान में क्रांति और कट्टरपंथी शिया हुकूमत आने के बाद सऊदी अरब दूसरे इस्लामिक देशों में कट्टर वहाबी आंदोलन को वैचारिक समर्थन मुहैया कराने के साथ ही फंडिंग भी उपलब्ध कराने लगा।